पार्षदों को जब माफ़ी मांगनी थी तो पानी के लिए नौटंकी की जरूरत क्या थी

एमसीएफ के अफसरो ने अपने काले कारनामे आंदोलन की आड़ में छिपाए

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में दो तीन दिनों तक चली नौटंकी से पार्षदों ने अपनी जो फजीहत कराई है, उससे उनकी बची-खुची साख खत्म हुई है। मामला पेयजल संकट से शुरू हुआ था, वह समस्या वहीं खड़ी हुई है। लेकिन इस समस्या को उठाने वाले जनता के चुने हुए पार्षदों को माफी मांगनी पड़ रही है। एमसीएफ के चंद निकम्मे अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों ने इस समस्या का समाधान करने की बजाय इस घटना की आड़ में कई सारे घोटालों पर पर्दा डाल दिया। शहर की तमाम समस्याओं को अब बेईमान अफसरों के सामने जनता के प्रतिनिधि उठाने का साहस नहीं कर पाएंगे।

इंजीनियर को बंधक क्यों बनाया

शहर में पिछले एक महीने से गंभीर पेयजल संकट चल रहा है। परेशान होकर 11 जुलाई को सेक्टर 25 के बूस्टर पंप पर वॉर्ड 3 के पार्षद जयवीर खटाना के नेतृत्व में भारी भीड़ ने धावा बोल दिया। वहां उन्होंने करीब तीन घंटे तक फरीदाबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) के एक्सईएन समेत कई अफसरों को बंधक बना लिया। आरोप है कि उन्होंने एफएमडीए के एक्सईएन मदनलाल के साथ बदसलूकी की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहां जनता का गुस्सा इस बात पर भड़का जब एफएमडीए के एक्सईएन मदनलाल ने कहा कि रैनीवेल से पानी तो आ रहा है लेकिन वहीं मौजूद एमसीएफ के इंजीनियर ने कहा कि पानी बूस्टर तक आ नहीं रहा तो सप्लाई कहां से होगी लेकिन मदनलाल इस बात पर अड़े रहे कि पानी तो आ रहा है। जनता ने मौके पर मदनलाल पर शराब पीने का आरोप लगाया। मौके पर जब एमसीएफ और एफएमडीए के अधिकारी हालात नहीं संभाल पाए तो पुलिस आई और पुलिस ने आश्वासन दिया कि दस दिनों में पानी आएगा। उसके बाद लोग चले गए।

एमसीएफ अफसरों ने बनाया मुद्दा

शहर को सही तरह से पानी सप्लाई न मिलने पर एफएमडीए और एमसीएफ के जिन अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए थी, उन्होंने अपने बचाव में रविवार की घटना की आड़ ले ली और कर्मचारी संगठनों को आगे करके एमसीएफ में हड़ताल करवा दी।

एमसीएफ का इंजीनियरिंग विंग सबसे भ्रष्ट विभाग है। कर्मतारी यूनियनों का इस विभाग से लेना-देना नहीं है लेकिन उन्होंने मुद्दा बना दिया। एक्सईएन मदनलाल एफएमडीए में अनुबंध पर हैं लेकिन एमसीएफ के कर्मचारी संगठनों ने दूसरी एजेंसी के इंजीनियर के मामले को तूल दे दिया। कर्मचारी संगठनों ने नगर निगम कमिश्नर से मांग की कि जब तक पार्षद जयवीर खटाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी।

अफसरों ने दबाव बनाया और 13 जुलाई को जयवीर खटाना के खिलाफ सेक्टर 55 पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसमें एससी-एसटी एक्ट भी लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने खटाना सहित इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वॉर्ड 3 की जनता ने नगर निगम अफसरों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करानी चाही तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

पार्षद खटाना की गिरफ्तारी की सूचना फैली तो मंगलवार शाम को पार्षदों ने भी कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कमिश्नर गरिमा मित्तल के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें हटाने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि क्या जनता के लिए पानी मांगना अपराध है। हम भी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। पार्षद देर रात तक एमसीएफ दफ्तर पर धरना देकर बैठे रहे।

14 जुलाई को हो गया माफीनामा

निगम कर्मचारियों की हड़ताल और पार्षदों की नौटंकी के बीच पर्दे के पीछे तमाम शक्तियां काम कर रही थीं कि किसी तरह मामला शांत हो जाए लेकिन निगम कर्मचारियों ने झुकने से मना कर दिया। तब पार्षदों को समझाकर समझौते के लिए राजी किया गया। 14 जुलाई को धरने पर बैठे कर्मचारियों के बीच पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना, उनके पार्षद भाई राकेश भड़ाना, निगम की अतिरिक्त कमिश्नर वैशाली शर्मा, जयवीर खटाना की मां, पूर्व मेयर आदि वहां अवतरित हुए। नागेन्द्र भड़ाना ने पार्षद जयवीर खटाना की ओर से माफी मांगी। कर्मचारी नेताओं ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौटने का ऐलान किया। पूर्व विधायक नागेन्द्र भड़ाना ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्षद और एमसीएफ के अधिकारी-कर्मचारी एक परिवार की तरह हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती। हमें मिलजुल कर काम करना है। हम लड़ेंगे तो हमारा नुकसान है। पूर्व विधायक नागेन्द्र भड़ाना के इस भाषण का सार कुल मिलाकर यह था कि अगर लड़ाई करेंगे तो पार्षदों के साथ-साथ अफसरों का सारा धंधा-पानी बंद हो जाएगा। इसलिए मिलजुलकर माल काटो।

इनका धन्यवाद क्यों

आंदोलन खत्म करने की घोषणा और माफी की घोषणा के बीच नागेन्द्र भड़ाना, पार्षदों और कर्मचारी नेताओं ने इस मामले को सुलझाने के लिए बार-बार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर और डीसी फरीदाबाद यशपाल यादव का धन्यवाद किया। कहा जा रहा है कि पार्षद जब नगर निगम दफ्तर पर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे थे तो वे लगातार गूजर और डीसी के संपर्क में थे। यही काम कर्मचारी नेता भी कर रहे थे। आसानी से समझा जा सकता है कि यहां डीसी यशपाल यादव ने अपनी लीडरशिप दिखाते हुए मामला सुलझवा दिया और चारों तरफ से आलोचना का शिकार कमिश्नर गरिमा मित्तल हुईं। मंत्री कृष्णपाल गूजर ने यह संकेत दिया कि पार्षद उनके इशारे पर ही सबकुछ करते हैं। पिछले दिनों कृष्णपाल ने पार्षदों और कमिश्नर गरिमा मित्तल के बीच बैठक कराई थी और उसमें सारे विवाद सुलझाने के दावे किए गए थे। सवाल यह है कि कमिश्नर गरिमा मित्तल क्यों बार-बार इन लोगों के निशाने पर आ रही हैं। क्या तमाम मामलों की जांच का आदेश करना, ठेकेदारों की पेमेंट रोकने की वजह से सभी शक्तियां मिलकर उनका विरोध कर रही हैं।

क्या शहर को पानी मिला

पार्षदों ने जो अपनी फजीहत कराई, उससे पेयजल संकट का मामला बहुत पीछे चला गया है। अगर सारे पार्षद एकजुट होते और समझदारी से काम लेते तो जनता को साथ लेकर पानी के मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे। लेकिन अफसरों को बंधक बनाकर उन्होंने मामले को उलझा दिया। इस घटना से जनता में उनकी बची-खुची साख भी खत्म हो गई है। सेक्टर 22, 23, 55, संजय कॉलोनी में इस समय पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग हजारों रुपये का पानी खरीद कर पी रहे हैं। पानी माफिया किसी न किसी तरीके से सरकारी पेयजल सप्लाई प्रभावित कर देता है और शहर का पानी बंद हो जाता है और उसका पानी बिकता है। वॉर्ड 3 के पार्षद जयवीर खटाना पर जनता का भारी दबाव बन गया था, तभी वो भीड़ को लेकर सेक्टर 25 के बूस्टर पर पहुंचे थे। मुद्दा सही था लेकिन अराजकता ने एक मुद्दे को पार्षदों की फजीहत में बदल दिया।

जनता को याद होगा, पिछले दिनों कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने वॉर्ड 6 के बूस्टर पंप पर रात को छापा मारा और उस घटना का फेसबुक लाइव हुआ। नीरज ने आरोप लगाया था कि वहां बीजेपी पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल और जेई राहुल तेवतिया बैठकर अन्य लोगों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे।

विधायक ने कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग की। जबकि पार्षद अग्रवाल ने उल्टा विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप लगा दिया। इस घटना के विरोध में भी भाजपा पार्षदों ने लामबंद होकर कमिश्नर को विधायक के घर की गली को तोड़े जाने का आदेश करा लिया था। इन सारी घटनाओं का विश्लेषण बताता है कि पानी की जब-जब समस्या शहर में खड़ी होती है, तब-तब कोई न कोई फालतू मुद्दा छेड़कर ध्यान मोड़ दिया जाता है। पार्षद से लेकर अधिकारी, कर्मचारी अपने मुद्दों और धंधे-पानी के लिए लामबंद हैं लेकिन जनता लामबंद नहीं हो पा रही है।

'मोदी को धन्यवाद' देने की आड़ में ठेकेदारों ने हजम कर लिए एमसीएफ के 8 करोड़

विज्ञापन एजेंसियों को कमिश्नर गरिमा मित्तल के नोटिस की परवाह नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के तीनों जोन में यूनीपोल और जेंट्री पर विज्ञापन लगाने वाली कंपनियों ने एमसीएफ को करीब 8 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया लेकिन शहर में मुफ्त वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देने के लिए लगाए गए होर्डिंग और यूनीपोल जरूर नजर आ रहे हैं। इस तरह मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने की आड़ में एमसीएफ का पैसा डूबने की कगार पर है।

क्या है सारा मामला

एमसीएफ ने तीन अलग-अलग विज्ञापन कंपनियों को एनआईटी जोन, ओल्ड जोन और बल्लभगढ़ जोन में यूनीपोल और जेंट्री पर विज्ञापन लगाने के लिए ठेका दिया था। जिन कंपनियों को ये ठेके दिए गए, वे हैं-एनआईटी में स्क्वायर आउटडोर सर्विस, ओल्ड फरीदाबाद जोन में श्याम एंटरप्राइजेज और बल्लभगढ़ जोन में ग्लोबल एडवरटाइजिंग इंडिया को ठेके दिए गए थे। इन्हें नई-नई साइट पर यूनिपोल और जेंटी विकसित करने, उसकी मार्केटिंग और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन इन तमाम कंपनियों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया।

इन विज्ञापन कंपनियों ने एमसीएफ के करीब आठ करोड़ रुपये डकार लिए। एनआईटी जोन में करीब चार करोड़, ओल्ड जोन में तीन करोड़ से ज्यादा और बल्लभगढ़ जोन में करीब साठ लाख रुपये बकाया हैं। विज्ञापन कंपनियां इन पैसों को देने का नाम नहीं ले रही हैं। इन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन किसी भी विज्ञापन कंपनी ने इन नोटिसों की परवाह नहीं की। अब एमसीएफ कमिश्नर गरिमा मित्तल ने इन सभी फर्मों को 30 दिनों का नोटिस देते हुए चेतावनी जारी की है।

एमसीएफ के अफसर कर रहे कमाई

विज्ञापन एजेंसियों को जब ठेके दिए गए थे तो उस समय यह काम तत्कालीन एक्सईएन ओमवीर सिंह को दिया गया था। उसके बाद ओमवीर सिंह एसई बन गए। बीच में एक दूसरे घोटाले के आरोप में ओमवीर सिंह निलम्बित भी किए गए थे लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया था। आरोप है कि जब विज्ञापन कंपनियों को ठेके दिए गए थे तो उस समय समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। समझौते की शर्तों में यह लाइन बदली हुई है कि अगर नगर निगम का पैसा डूबा तो वह इन विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। अब जैसे कमिश्नर गरिमा मित्तल ने जो अंतिम चेतावनी 30 दिनों का नोटिस भेजते हुए दी है, अगर ठेकेदार पैसा जमा नहीं कराते हैं तो एमसीएफ क्या कार्रवाई कर सकता है। समझौते की शर्तों के मुताबिक एमसीएफ ज्यादा से ज्यादा इनके ठेके रद्द कर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकता है। विज्ञापन एजेंसियां यही चाह रही है। हर एजेंसी ने कई करोड़ रुपये डकारे हुए हैं। ठेका कैंसल होने पर जब दोबारा ठेका उठेगा तो वो नए नामों से ठेका उठा लेंगी। यह इस तरह का मायाजाल है जिसमें सिर्फ एमसीएफ के अफसर और विज्ञापन कंपनियां मलाई काटती हैं। जबकि एमसीएफ कंगाल होता जा रहा है। एमसीएफ के विज्ञापन घोटाले में कमिश्नर गरिमा मित्तल ने विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली लेकिन उन अफसरों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जो एमसीएफ का पैसा डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। कमिश्नर चाहतीं तो इस घोटाले की जांच कराकर हरियाणा सरकार को सूचित कर सकती थीं। जैसा उन्होंने पहले भी किया है और ऊपर के अफसरों ने ऐसे मामलों को दबा दिया।

ठेकेदारों को राजनीतिक संरक्षण

एमसीएफ के लिए काम करने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यह काम इतने संगठित तरीके से किया जा रहा है कि इसमें कई नेता मोटी कमाई कर रहे हैं। कांग्रेस के जाने के बाद इस काम को बीजेपी नेताओं ने संभाल लिया है। यहां हम सड़क, सीवर, पानी, पार्कों में जिम, फैंसी लाइट लगाने के काम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ विज्ञापन एजेंसी के ठेकेदारों की। शहर में आपको इन दिनों और जब-तब तमाम चौराहों, मुख्य सड़कों, पार्कों के आसपास यूनीपोल और जेंट्री पर बीजेपी नेताओं के होर्डिंग, फ्लेक्सी बोर्ड नजर आते होंगे। ये सभी विज्ञापन मुफ्त में लगते हैं। विज्ञापन

ठेकेदार इन्हें फटीक बोलते हैं। यह अलग बात है कि जिला भाजपा इनके खर्चे अपने हिसाब में दिखाती हो। बहरहाल, इस समय आपको मुफ्त वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए होर्डिंग शहर में नजर आ रहे होंगे।

इस होर्डिंग में फरीदाबाद की जनता की ओर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। जनता यह पहले से जानती है कि मुफ्त वैक्सीन केंद्र सरकार ने की है लेकिन नेताओं को शोशेबाजी की आदत है। बहुत संभव है कि ये होर्डिंग केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल की ओर से भी न लगाए गए हों, बल्कि उनके किसी चमचे या खुद विज्ञापन ठेकेदार ने जानबूझकर लगाए हों। सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन ठेकेदारों ने आपस में गठजोड़ बनाते हुए एमसीएफ को बकाया न चुकाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा है कि वे उनके मुफ्त में होर्डिंग लगाते हैं तो उसकी कीमत ऐसे ही वसूली जाएगी। इसलिए उन्हें उनका राजनीतिक संरक्षण चाहिए। नेताओं की ओर से उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई है।